

रैजिस्ट्रं नं० पी०/एस० एम० 14.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 15 मई, 1987/25 वैशाख, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(ख-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 जनवरी, 1987

नं० जी० ए० बी०-1 ए (4) 4/84.—हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लैंड रैवन्यू ऐक्ट, 1954 (1954 का 6) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश जिला मण्डी में एक नई उप-तहसील कोटली के सृजन का जिसका मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारिता उसके सामने दर्शित की गई है,

तुरन्त आदेश देते हैं :—

अधिकारिता

क्र०स०	तहसील का नाम	नई सृजित उप-तहसील का नाम	मुख्यालय	पटवार वृत्तों के नाम
1.	मण्डी सदर	कोटली	कोटली	(1) कडकोह (2) बरनोट (3) सरवाडी (4) समराहन (5) कोटली (6) भरगांव (7) कोट (8) नालसन (9) साईगल (10) कुटली (11) सेहली

आदेश द्वारा,
पी० के० मट्टू,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Government Notification No. GAB-1A(4)4/84, dated 28th January, 1987 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th January, 1987

No. GAB-1A(4)4/84.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act 6 of 1954), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the creation of new Sub-Tehsil Kotli, in Mandi district with the headquarter and territorial jurisdiction shown against it below, with immediate effect:—

JURISDICTION

Sr. No.	Name of the Tehsil	Name of the newly created Sub-Tehsil	Headquarters	Name of the Patwar Circle
1.	Mandi Sadar	Kotli	Kotli	(1) Karkoh (2) Barnota (3) Sarwari (4) Samrahan (5) Kotli (6) Bhargaun (7) Kot (8) Nalsan (9) Saiglu (10) Kutli (11) Sehli

By order,
P. K. MATTOO,

श्रम, रोजगार तथा मूद्रण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मार्च, 1987

संख्या 2-22/85 श्रम.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित समस्त “सिचाई उद्योग” की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम सं० 14) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु जनोपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

2. और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह भी प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं को जनोपयोगी सेवा छः (6) महीने तक करना अनिवार्य है।

3. अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खण्ड (एन) के उप-खण्ड (VI) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थित समस्त ‘सिमिन्ट उद्योग’ की सेवाओं को जनोपयोगी सेवा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छः (6) मास तक की अवधि के लिए सहस्रं तुरन्त घोषित करते हैं।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[In pursuance of clause (3) of Article 348 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the English text of Notification No. LSG 7-53/67-III, dated 24-2-1987 for the general information of the public].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th February, 1987

No. LSG.7-53/67-III.—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (i) of section 257, of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following official and non-official member of the Notified Area Committee, Nagrota Bagwan in District for a period of three years, with immediate effect:—

Official Members

Non-official Members

- | | |
|--|---|
| 1. Sub-Divisional Magistrate, President | 1. Shri Harbhagwan Khosla s/o Shri Sudama Mull. |
| 2. Assistant Engineer, Himachal Pradesh Public Works Deptt. (B&R) Nagrota Bagwan. | 2. Shri Laxmi Chand Mehta s/o Shri Birbal Mehta. |
| 3. Asstt. Engineer, H.P. State Electricity Board, Nagrota Bagwan. | 3. Shri Pardeep Kumar Gupta s/o Shri Roshan Lall. |
| 4. Asstt. Engineer, H.P. Public Works Department, Nagrota Bagwan (Irrigation and Public Health). | 4. Shri Atma Ram Mehra s/o Shri Lehnuram. |

5. Medical Officer, Incharge, Primary Health Centre, Nagrota Bagwan.

5. Shri Suraj Prakash s/o Shri Ishwar Dass.
6. Shri Roshan Lall s/o Shri Bihari Lall.
7. Shri Pritam Chand s/o Shri Dogru Ram Harijan Kir Chamba.
8. Shri Satish Kumar Sarotri s/o Shri Prem Lal, Sarotri.

By order,
Sd/-
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 17 मार्च, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 84/86.—क्योंकि ग्राम पंचायत डरवाड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, ने अपने प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 12-7-1986 में यह सूचित किया है कि श्री पृथी पाल, पंच, ग्राम पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं।

क्योंकि उपरोक्त विषय की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वे अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मण्डी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 मार्च, 1987

संख्या 3-15/85-ई0एल0एन—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/84-XXXI, दिनांक 4 मार्च, 1987, तदनुसार 13 फाल्गुन, 1908 (शक्), हिन्दी रूपान्तर सहित सर्व साधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित करता हूँ।

आदेश से,
अत्तर सिंह,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi:
the 4th March, 1987
Dated Phalguna 13, 1908 (S)

NOTIFICATION

S.O.—Whereas the Election Commission of India is satisfied that as a result of its poll performance at the general election to the Legislative Assembly held in February, 1987, in the State of Mizoram the Mizo National Front is entitled for registration and recognition as a

State Party in the State of Mizoram in terms of paragraph 3 and 6 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

And whereas the Commission has decided to recognise the Mizo National Front as a State Party in the State of Mizoram and reserve the symbol "Tiger" for the said party in that State;

Now, therefore, in pursuance of clause (b) and (d) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/84-I, dated the 13th November, 1984, published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3(iii), dated the 16th November, 1984, as amended from time to time, namely:—

(1) In Table 2 of the said notification, against the State of Mizoram, under columns 2 and 3 of the Table, for the entry "People's Conference.....Scales", the following entries shall be substituted:—

"(1) Mizo National Front.....Tiger
2. People's Conference.....Scales".

(2) In Table 4 of the said notification, against item No. 30. Mizoram mentioned in column 1 thereof the entry "17.Tiger" specified in column 2 thereof shall be deleted and the existing entry "18" shall be renumbered as "17".

The recognition granted to the above-mentioned political party is subject to the following conditions:—

- (i) the party shall communicate to the Commission without delay any change in its name and head office, office bearers and their addresses and political principles policies and objectives and any change any other material matters;
- (ii) the party shall intimate the Commission immediately whenever any amendments are issued to party constitution along with the relevant documents like the notice for the meeting, minutes of the meeting where the amendments have been carried etc.
- (iii) the party shall maintain all the records like minutes books, accounts books, membership register, receipt books, etc. properly;
- (iv) the said records shall be open for inspection at any time by the authorised representative(s) of the Commission; and
- (v) the recognition granted shall be reviewed by the Commission from time to time.

[No. 56/84-XXXI]

By order,
R. P. BHALLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली:
4 मार्च, 1987

तारीख—
13 फाल्गुन, 1908 (शक्)

अधिसूचना

का 0 आ 0.—भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 3 तथा 6 के अनुसार मिजोरम राज्य से विधान सभा के लिए फरवरी, 1987 में हुए साधारण

निर्वाचन में प्राप्त किए गए अपने मतों के परिणाम स्वरूप मिजो नैशनल फ्रंट मिजोरम राज्य में एक राज्यीय दल के रूप में पंजीकरण तथा मान्यता प्राप्त करने के लिए हकदार हैं;

और आयोग ने मिजो नैशनल फ्रंट के मिजोरम राज्य में एक राज्यीय दल के रूप में मान्यता देने और राज्य में उक्त दल के लिए "चीता" निर्वाचन-प्रतीक अरक्षित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक (अरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) और (घ) तथा उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II खण्ड 3 (III), दिनांक 16 नवम्बर, 1984 में प्रकाशित और समय-समय पर यथा-संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 56/84-I, दिनांक 13 नवम्बर, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:—

- (1) उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में मिजोरम राज्य के सामने, सारणी के स्तम्भ 2 और 3 के अधीन "पीपुल्स कांफ्रेंस तराजू" प्रविष्टि के स्थान पर:—
 "1. मिजो नैशनल फ्रंट चीता
 2. पीपुल्स कांफ्रेंस तराजू"
 प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (2) उक्त अधिसूचना की सारणी 4 में, स्तम्भ 1 में उल्लिखित मद सं० 30 मिजोरम के सामने, उसके स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि "17. चीता" को हटा दिया जाएगा और विद्यमान प्रविष्टि "18" को पुनः संख्यांकित करके "17" कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त राजनैतिक दल को प्रदत्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है:—

- (1) दल, बिना देरी किए निर्वाचन आयोग को अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पदाधिकारियों के पते और राजनैतिक सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में सूचित करेगी;
- (2) दल, जब कभी दल के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो उसकी सूचना सुसंगत दस्तावेजों जैसे संशोधनों पर विचारार्थ बैठक की सूचना, बैठक के लिए कार्यसूची, उस बैठक का कार्यवृत्त जिसमें संशोधन किए गए, आदि के साथ तत्काल निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा;
- (3) दल सभी अभिलेखों जैसे कार्यवृत्त पुस्तकों, लेखा बहियों, सदस्यता रजिस्ट्रों, रसीद बहियों आदि का समुचित रूप से रख-रखाव करेगा;
- (4) निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उक्त अभिलेखों का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा; और
- (5) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मान्यता का समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाएगा।

[संख्या 56/84-31]

आदेश से,
 आर० पी० भल्ला,
 सचिव।